CA 14th May, 2022 (HINDI)

CS MENTORS
civil services MENTORS
IAS ACADEMY

मई- 2022

CS Mentors | SCO 13-14-15, 3rd Floor, Sector-34A, Chandigarh.
Contact: (+91) 8822299444.**Website:** www.thecsmentors.com

Topics

1. देशद्रोह पर कानून
2. मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
3. जम्मू-कश्मीर परिसीमन रिपोर्ट
4. खबरों में रोग
5. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022
6. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए)
7. एक लाइनर

CS Mentors IAS Academy

देशद्रोह पर कानून

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने अपराध से निपटने वाली धारा 124ए के प्रावधानों पर फिर से विचार करने और पुनर्विचार करने का फैसला किया है और कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उचित मंच के समक्ष सुनवाई तब तक टालने का आग्रह किया जब तक कि इस तरह की कवायद नहीं की जाती।

राजद्रोह पर कानून (धारा 124ए)

- ✓ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए, राजद्रोह से संबंधित है। यह थॉमस बबिंगटन मैकाले द्वारा तैयार किया गया था और 1870 में आईपीसी में शामिल किया गया था।
- ✓ इसमें कहा गया है कि 'जो कोई, शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, घृणा या अवमानना में लाने का प्रयास करता है, या उत्तेजित करता है या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, द्वारा स्थापित सरकार कानून, कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है।'
- ✓ राजद्रोह एक गैर-जमानती अपराध है। कानून के तहत सजा तीन साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक होती है।

धारा 124ए पर पिछले निर्णय

- ✓ **केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में प्रदान किए गए अनुसार स्वतंत्र भाषण पर एक उचित प्रतिबंध के रूप में नोट किया।
- ✓ इसने स्पष्ट किया कि एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह आलोचना या टिप्पणियों के माध्यम से सरकार या उसके उपायों के बारे में जो कुछ भी पसंद करती है उसे कहने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाती नहीं है।
- ✓ **केदार नाथ मामले** के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी (2012) के मामले में दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पुलिस को राजद्रोह के प्रावधानों को लागू करने से पहले पालन करना चाहिए।
- ✓ इनमें सामग्री का एक वस्तुपरक मूल्यांकन शामिल है जो इस पर एक राय बनाने के लिए है कि क्या शब्द और कार्य सरकार के प्रति अरुचि, शत्रुता और बेवफाई का कारण बनते हैं क्योंकि वे इस परिमाण के होने चाहिए कि वे हिंसा को भड़काते हैं या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करते हैं।
- ✓ न्यायालय ने जिले के एक विधि अधिकारी से लिखित रूप में कानूनी राय प्राप्त करने का भी निर्देश दिया, जो पूर्व-शर्तों को पूरा करने के बारे में कारण बताए।
- ✓ इसके बाद राज्य के लोक अभियोजक से दूसरी राय लेने की आवश्यकता है।

कानून की समीक्षा करने के कारण

- ✓ 1860 के दशक में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासकों द्वारा इसे लागू किए जाने के बाद से राजद्रोह कानून बहस में है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित कई शीर्ष स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं पर राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
- ✓ महात्मा गांधी ने इसे "नागरिक की स्वतंत्रता को दबाने के लिए डिज़ाइन किए गए भारतीय दंड संहिता के राजनीतिक वर्गों के बीच राजकुमार" के रूप में वर्णित किया।

CS Mentors IAS Academy

- ✓ कई मौकों पर अदालतों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद, कानून प्रवर्तन एजेंसियां राजद्रोह के प्रावधानों का दुरुपयोग करना जारी रखती हैं और अदालत के निर्देशों की अनदेखी करती हैं। इसलिए समस्या कानून और दिशानिर्देशों के खराब कार्यान्वयन में है।
- ✓ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर, 2016 और 2019 के बीच, धारा 124ए के तहत देशद्रोह के मामलों की संख्या में 160% की वृद्धि हुई, जबकि दोषसिद्धि की दर 2016 में 33.3% से गिरकर 2019 में 3.3% हो गई।
- ✓ विशेष रूप से, इन मामलों में से कई आरोप देशद्रोह के दायरे से बाहर हैं। नतीजतन, चौंका देने वाली संख्या ने लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि "उद्देश्य किसी को दंडित या दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि उन्हें कैद करना है ... प्रक्रिया ही सजा है।"
- ✓ यह डेटा और कानूनी प्रावधानों का घोर दुरुपयोग किसी को यह कहने के लिए मजबूर करता है कि भले ही एक संविधान पीठ ने राजद्रोह के कानून के अधिकार को बरकरार रखा हो, परिस्थितियों को अब प्रावधान पर पूरी तरह से पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- ✓ जब स्थिति बदलती है, तो क़ानून बदलाव की मांग करता है क्योंकि कानून स्थिर रहने का जोखिम नहीं उठा सकता है।
- ✓ यू.के. ने 2010 में राजद्रोह के अपराध को निरस्त कर दिया है और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अवशेष पर कब्जा कर रहा है।
- ✓ राजद्रोह पर अपने परामर्श पत्र में, भारत के विधि आयोग ने कहा कि सरकार की असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में एक मजबूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्व हैं।
- ✓ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान ने सुझाव दिया कि यह धारा 124ए पर पुनर्विचार करने या यहां तक कि निरस्त करने का समय है।

मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) के पार्टियों के सम्मेलन (COP15) के पंद्रहवें सत्र में अपने संबोधन के दौरान पर्यावरण के लिए जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया।

COP15 9 से 20 मई 2022 तक कोटे डी आइवर के आबिदजान में आयोजित किया जा रहा है। यह सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और दुनिया भर के अन्य प्रमुख हितधारकों के नेताओं को भविष्य के भूमि स्थायी प्रबंधन में प्रगति के लिए एक साथ लाएगा और भूमि और अन्य प्रमुख स्थिरता मुद्दों के बीच संबंधों का पता लगाएगा।

मंत्री ने आगे कहा कि भारत ने पूरे देश में लागू किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के माध्यम से अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी में वृद्धि की है। 2015 और 2019 के बीच किसानों को 229 मिलियन से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं और इस कार्यक्रम से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8-10% की गिरावट आई है और उत्पादकता में 5-6% की वृद्धि हुई है।

मरुस्थलीकरण

- ✓ मरुस्थलीकरण शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि क्षरण की एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन जैसे लंबे समय तक सूखे और बाढ़ सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती है।
- ✓ यह अवधारणा मौजूदा रेगिस्तानों के भौतिक विस्तार को संदर्भित नहीं करती है, बल्कि विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित है जो सभी शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्रों के लिए खतरा हैं।

भूमि क्षरण और भूमि मरुस्थलीकरण

- ✓ भूमि क्षरण कई ताकतों के कारण होता है, जिसमें चरम मौसम की स्थिति विशेष रूप से सूखा, और मानवीय गतिविधियाँ शामिल हैं जो मिट्टी और भूमि उपयोगिता की गुणवत्ता को प्रदूषित या ख़राब करती हैं जो खाद्य उत्पादन, आजीविका, और अन्य पारिस्थितिक तंत्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और प्रावधान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।
- ✓ मरुस्थलीकरण को "एक प्रकार की भूमि क्षरण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक अपेक्षाकृत शुष्क भूमि क्षेत्र तेजी से शुष्क हो जाता है, आमतौर पर पानी के साथ-साथ वनस्पति और वन्य जीवन को भी खो देता है।"

यूएनसीसीडी

- ✓ संयुक्त राष्ट्र के तीन प्रमुख सम्मेलन हैं: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी)।
- ✓ ये सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का परिणाम थे, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है।
- ✓ 1994 में स्थापित, UNCCD पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- ✓ कन्वेंशन विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां कुछ सबसे कमजोर पारिस्थितिक तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं।
- ✓ UNCCD का कार्यान्वयन पाँच क्षेत्रीय कार्यान्वयन अनुबंधों के आसपास तैयार किया गया है: अफ्रीका के लिए अनुलग्नक 1, एशिया के लिए अनुलग्नक 2, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए अनुलग्नक 3, उत्तरी भूमध्यसागरीय के लिए अनुलग्नक 4 और मध्य और पूर्वी यूरोप के लिए अनुलग्नक 5।
- ✓ ये अनुबंध विशेष उप-क्षेत्रों और क्षेत्रों के लिए कार्य कार्यक्रमों के फोकस और सामग्री को निर्धारित करने के लिए हैं। वे क्षेत्रीय समन्वय और सहयोग के लिए एक ढांचा भी प्रदान करते हैं।
- ✓ कन्वेंशन में भारत सहित 197 पार्टियां हैं।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन रिपोर्ट

कई आपत्तियों और विस्तार के बाद, जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा निर्धारित जनादेश के अनुसार जम्मू और कश्मीर में चुनावी सीमाओं को फिर से बनाने के लिए नियुक्त किए जाने के दो साल बाद, 5 मई, 2022 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अपने आदेश में, जिसकी एक अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तीन सदस्यीय पैनल ने अधिनियम के अनुसार जम्मू क्षेत्र के लिए अतिरिक्त छह और कश्मीर घाटी के लिए एक अतिरिक्त विधानसभा सीटें बनाईं। आयोग के अंतिम आदेश ने पूर्ववर्ती राज्य में चुनावों के लिए मंच तैयार किया है, जहां पिछली बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे।

परिसीमन क्या है?

- ✓ परिसीमन लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसांख्यिकीय स्थिति में बदलाव के अनुसार की जाती है। परिसीमन एक परिसीमन आयोग या सीमा आयोग द्वारा किया जाता है।

CS Mentors IAS Academy

- ✓ स्वतंत्र निकाय के आदेशों पर किसी भी अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अतीत में, परिसीमन आयोग 1952, 1963, 1973 और 2002 में स्थापित किए गए थे।
- ✓ जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले, जम्मू और कश्मीर संविधान और जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 द्वारा इसकी विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया था। इस बीच, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन , संविधान द्वारा शासित था।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग

आखिरी बार जम्मू और कश्मीर में परिसीमन अभ्यास 1995 में 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था। उस समय जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। घाटी में तनावपूर्ण स्थिति के कारण 1991 में जम्मू-कश्मीर में कोई जनगणना नहीं हुई थी। 2001 में, जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने 2026 तक परिसीमन प्रक्रिया को रोकने के लिए एक कानून पारित किया।

जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित होने के छह महीने बाद, केंद्र ने मार्च 2020 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया।

आयोग को 2011 की जनगणना के आधार पर और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम सौंपा गया था।

अंतिम रिपोर्ट के मुख्य अंश

- ✓ सबसे पहले, जम्मू और कश्मीर को दो डिवीजनों में विभाजित किया गया है, जम्मू में 37 विधानसभा सीटें और कश्मीर 46 हैं। आयोग के अंतिम मसौदे के बाद, जम्मू के लिए छह अतिरिक्त विधानसभा सीटें (43 में संशोधित) और कश्मीर के लिए एक (47 में संशोधित) निर्धारित की गई हैं। यूटी में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी।
- ✓ दूसरा, आयोग ने केंद्र से विधानसभा के लिए कम से कम दो कश्मीरी पंडितों को मनोनीत करने की सिफारिश की है। तीसरा, पैनल ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए नौ सीटों का प्रस्ताव किया है।
- ✓ चौथा, आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों को नामांकन के माध्यम से विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने पर विचार करे।
- ✓ केंद्र अब एक तारीख तय करेगा जिससे परिसीमन आदेश प्रभावी होगा। यह 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिए जाने के बाद बहुप्रतीक्षित पहले विधानसभा चुनावों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

खबरों में रोग

केरल के स्वास्थ्य विभाग ने कासरगोड में खाद्य विषाक्तता की घटना के कारण शिगेला बैक्टीरिया की पहचान की, जिसमें एक 16 वर्षीय लड़की की मौत हो गई।

- ✓ शिगेला बैक्टीरिया एंटरोबैक्टर परिवार से संबंधित है - बैक्टीरिया का एक समूह जो आंत में रहता है, जो सभी मनुष्यों में बीमारी का कारण नहीं बनता है।

CS Mentors IAS Academy

- ✓ यह भोजन और जल जनित संक्रमण का कारण बनता है जो मुख्य रूप से आंत को प्रभावित करता है और इसके परिणामस्वरूप दस्त (कभी-कभी खूनी), पेट दर्द और बुखार होता है।
- ✓ **फैलाना** - संक्रमण आसानी से फैलता है क्योंकि किसी को बीमार करने के लिए बहुत कम संख्या में बैक्टीरिया लगते हैं।
- ✓ यह तब हो सकता है जब कोई दूषित भोजन, बिना धुले फल या सब्जियों का सेवन करता है।
- ✓ यह रोगी के मलमूत्र के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से आसानी से फैलता है।
- ✓ शिगेलोसिस टाइफाइड और हैजा की तरह बहुत आम संक्रमण नहीं है।
- ✓ **प्रकार** - शिगेला बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं जो मनुष्यों को प्रभावित करते हैं - शिगेला सोनेई, एस. फ्लेक्सनेरी, एस. बॉयडी, और एस. पेचिश (dysenteriae)।
- ✓ चौथा प्रकार सबसे गंभीर बीमारी का कारण बनता है क्योंकि यह विष पैदा करता है।
- ✓ लेकिन लोगों का संक्रमण से मरना आम बात नहीं है, जब तक कि
- ✓ रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है या
- ✓ रोगज़नक़ उन एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी है जो निर्धारित हैं या
- ✓ गर्भावस्था के दौरान और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में शिगेला का प्रकोप तेज होता है।
- ✓ **उपचार** - शिगेलोसिस एक बहुत ही उपचार योग्य स्थिति है; यदि कोई मरीज समय पर अस्पताल पहुंचता है तो IV एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करके उसका प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है।
- ✓ समस्या तब होती है जब एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते क्योंकि बैक्टीरिया इसके प्रतिरोधी होते हैं।
- ✓ **समस्या** - अगर एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी बैक्टीरिया शरीर में पनपता रहता है, तो यह विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता रहेगा जो अन्य सभी अंगों को प्रभावित कर सकते हैं।
- ✓ ये टॉक्सिन्स तब किडनी को प्रभावित कर सकते हैं, दौरे का कारण बन सकते हैं, मल्टी-ऑर्गन फेलियर और शॉक का कारण बन सकते हैं और यहां तक कि घातक भी हो सकते हैं।
- ✓ संक्रमण से मृत्यु दर 1% से कम है।
- ✓ **सावधानियां** - शिगेला संक्रमण को रोकने के उपाय वही हैं जो किसी भी अन्य खाद्य- और जल जनित संक्रमण के समान हैं - स्वच्छ रहें।
- ✓ दूध, चिकन और मछली जैसे उत्पाद आसानी से संक्रमित हो सकते हैं और उन्हें उचित तापमान पर रखा जाना चाहिए। उन्हें भी ठीक से पकाया जाना चाहिए।

मंकीपॉक्स

- ✓ हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम में स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक व्यक्ति में मंकीपॉक्स के मामले की पुष्टि की है, जो चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है, जिसने हाल ही में नाइजीरिया से उस देश की यात्रा की थी।
- ✓ मंकीपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, जो वायरस का एक जीनस है जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है, जो चेचक का कारण बनता है, और वैक्सीनिया वायरस, जिसका उपयोग चेचक के टीके में किया गया था।
- ✓ मंकीपॉक्स चेचक के समान लक्षण पैदा करता है, हालांकि वे कम गंभीर होते हैं।
- ✓ 1980 में टीकाकरण से दुनिया भर में चेचक का उन्मूलन हो गया, जबकि मध्य और पश्चिम अफ्रीका के देशों में मंकीपॉक्स का प्रकोप जारी है, और कभी-कभी यह कहीं और दिखाई देता है।

CS Mentors IAS Academy

- ✓ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दो अलग-अलग क्लैड की पहचान की गई है: वेस्ट अफ्रीकन क्लैड और कांगो बेसिन क्लैड, जिसे सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड के रूप में भी जाना जाता है।
- ✓ संचरण, जब यह होता है, शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क के माध्यम से हो सकता है, त्वचा पर घाव या आंतरिक म्यूकोसल सतहों, जैसे मुंह या गले में, श्वसन बूंदों और दूषित वस्तुओं पर हो सकता है।

टमाटर फ्लू

- ✓ केरल में "टमाटर फ्लू" के मामलों का पता चलने के मद्देनजर तमिलनाडु ने अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है।
- ✓ टमाटर फ्लू या बुखार एक वायरल रोग है। फ्लू का नाम लाल छाले के कारण पड़ा है।
- ✓ बुखार पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है।
- ✓ लक्षणों में लाल चकत्ते, त्वचा में जलन और निर्जलीकरण शामिल हैं।
- ✓ इसमें थकान, जोड़ों का दर्द, पेट में ऐंठन, जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, खाँसी, छींकना, नाक बहना, तेज़ बुखार और शरीर में दर्द भी शामिल हैं।
- ✓ कुछ मामलों में, यह पैरों और हाथों का रंग भी बदल सकता है।
- ✓ **फैलाव** - फ्लू के अन्य मामलों की तरह, टमाटर बुखार भी संक्रामक है।
- ✓ अगर कोई इस फ्लू से संक्रमित है, तो उसे अलग-थलग रखने की जरूरत है क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल सकता है।
- ✓ बच्चों को फ्लू के कारण होने वाले फफोले को खरोंचने से रोकने के लिए यह आवश्यक है। उचित आराम और स्वच्छता की भी सलाह दी जाती है।
- ✓ **उपचार** - टमाटर फ्लू एक आत्म-सीमित है और इसके लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है।
- ✓ इसका अर्थ यह है कि यदि सहायक देखभाल दी जाती है तो लक्षण अपने आप ओवरटाइम ठीक हो जाएंगे।
- ✓ तरल पदार्थ का सेवन भी निर्जलीकरण का मुकाबला करने में मदद करेगा।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022

- ✓ हाल ही में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (WPFI) 2022 का 20वां संस्करण प्रकाशित किया गया था।
- ✓ यह 2002 से ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर (आरएसएफ) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- ✓ यह पत्रकारों के लिए उपलब्ध मीडिया स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है।
- ✓ यह मीडिया की स्वतंत्रता के मूल्यांकन पर आधारित है जो बहुलवाद, मीडिया स्वतंत्रता, मीडिया वातावरण और आत्म-सेंसरशिप, पारदर्शिता, और कानूनी ढांचे और पत्रकारों की सुरक्षा को मापता है।
- ✓ यह बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर भी आधारित है जो समाचार और सूचना के उत्पादन का समर्थन करता है।
- ✓ इसमें प्रत्येक क्षेत्र में मीडिया स्वतंत्रता उल्लंघन के स्तर के संकेतक शामिल हैं।
- ✓ **कार्यप्रणाली** - सूचकांक की रैंकिंग 0 से 100 के बीच के स्कोर पर आधारित होती है जिसे प्रत्येक देश या क्षेत्र को सौंपा जाता है।
- ✓ 100 सर्वोत्तम संभव स्कोर है (प्रेस स्वतंत्रता का उच्चतम संभव स्तर) और 0 सबसे खराब है।

CS Mentors IAS Academy

- ✓ देशों का मूल्यांकन पांच प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है - राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा।
- ✓ **निष्कर्ष** - 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से गिरकर 150 हो गई है।

Country	Rank in World Press Freedom Index 2022
Norway	1
Denmark	2
Sweden	3
India	**150 (142 in the year 2021)**
North Korea	180

- ✓ वैश्विक रुझानों के संदर्भ में, रिपोर्ट में ध्रुवीकरण में दो गुना वृद्धि को सूचना अराजकता द्वारा बढ़ाया गया है
  - ➢ मीडिया ध्रुवीकरण देशों के भीतर विभाजन को बढ़ावा दे रहा है, और
  - ➢ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच ध्रुवीकरण।
- ✓ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में, "पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया और मीडिया स्वामित्व की एकाग्रता सभी दर्शाती है कि प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है"।
- ✓ यह भारत को मीडिया के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताता है।
- ✓ यह नोट करता है कि पत्रकारों को पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा घात लगाकर, और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा घातक प्रतिशोध सहित सभी प्रकार की शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- ✓ यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि "हिंदुत्व के समर्थक, वह विचारधारा जिसने हिंदू दूर-दराज़ को जन्म दिया, अपनी सोच के विपरीत किसी भी विचार पर चौतरफा ऑनलाइन हमले करते हैं।"

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए)

सीबीआई ने गृह मंत्रालय (एमएचए) के विदेश विभाग के छह अधिकारियों से कुछ गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत मंजूरी देने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में पूछताछ की है।

एफसीआरए

- ✓ एफसीआरए 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के बीच अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं।
- ✓ कानून का उद्देश्य व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करना है ताकि वे एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सकें।
- ✓ राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए उनके उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए 2010 में कानून में संशोधन किया गया था।
- ✓ 2020 में इसे फिर से संशोधित किया गया, जिससे सरकार को गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण और जांच मिली।

अधिनियम की विशेषताएं- एफसीआरए के लिए विदेशी चंदा प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ की आवश्यकता होती है

- अधिनियम के तहत पंजीकृत
- भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में विदेशी धन की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता खोलने के लिए
- उन निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है और जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है
- वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए और किसी अन्य एनजीओ को धन हस्तांतरित नहीं करने के लिए

✓ यह अधिनियम उम्मीदवारों, पत्रकारों या समाचार पत्रों और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों, विधायिका के सदस्यों और राजनीतिक दलों या उनके पदाधिकारियों, और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों के लिए विदेशी धन की प्राप्ति को प्रतिबंधित करता है।

FCRA पंजीकरण कैसे प्रदान किया जाता है?

- ✓ एफसीआरए पंजीकरण उन व्यक्तियों या संघों को दिए जाते हैं जिनके पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं।
- ✓ गैर सरकारी संगठन जो विदेशी धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ✓ **प्राधिकरण**- गृह मंत्रालय आवेदक के पूर्ववृत्त में इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से पूछताछ करता है और 90 दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करता है।
- ✓ दिए गए समय में आवेदन को संसाधित करने में विफलता के मामले में, गृह मंत्रालय से एनजीओ को इसके कारणों के बारे में सूचित करने की अपेक्षा की जाती है।
- ✓ **पात्रता**- एफसीआरए के तहत, आवेदक
  - काल्पनिक या बेनामी नहीं होना चाहिए
  - एक धार्मिक आस्था से दूसरे धर्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रलोभन या बल के माध्यम से धर्मांतरण के उद्देश्य से गतिविधियों में लिप्त होने के लिए मुकदमा या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था
  - सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए था या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था
  - धन के दुरूपयोग या दुरूपयोग का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए था
  - देशद्रोह के प्रचार में लिप्त या संलिप्त होने की संभावना नहीं होनी चाहिए
- ✓ **वैधता**- एक बार प्रदान किए जाने के बाद, एफसीआरए पंजीकरण पांच साल के लिए वैध होता है और गैर सरकारी संगठनों से पंजीकरण की समाप्ति की तारीख के छह महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की उम्मीद की जाती है।
- ✓ नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफलता के मामले में, पंजीकरण समाप्त हो गया माना जाता है।

अनुमोदन रद्द करने के आधार

- ✓ **रद्दीकरण**-पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किया जा सकता है
  - अगर यह अधिनियम के उल्लंघन में पाया जाता है
  - अगर जांच में आवेदन में गलत बयान मिलता है
  - यदि एनजीओ को प्रमाण पत्र या नवीनीकरण के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करते पाया जाता है
  - यदि यह लगातार दो वर्षों से समाज के लाभ के लिए अपने चुने हुए क्षेत्र में किसी भी उचित गतिविधि में संलग्न नहीं है
  - अगर यह निष्क्रिय हो गया है

CS Mentors IAS Academy

- ➢ यदि केंद्र सरकार की राय में जनहित में प्रमाण पत्र को रद्द करना आवश्यक है
- ➢ यदि कोई लेखापरीक्षा विदेशी निधियों के दुरूपयोग के संदर्भ में वित्त में अनियमितताओं का पता लगाता है

✓ संबंधित व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है।

✓ **पुन: पंजीकरण-** एक बार किसी गैर सरकारी संगठन का पंजीकरण रद्द हो जाने के बाद, यह तीन वर्षों के लिए पुन: पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होता है।

✓ **निलंबन** - मंत्रालय के पास 180 दिनों तक लंबित जांच के लिए एक एनजीओ के पंजीकरण को निलंबित करने की शक्ति है, और इसके फंड को फ्रीज कर सकता है।

✓ सरकार के सभी आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

✓ 2011 तक, भारत में FCRA के तहत 40,000 से अधिक NGO पंजीकृत थे, लेकिन अब यह संख्या 16,000 है।

✓ पिछले सात वर्षों में, सरकार ने 16,700 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है।

✓ एमनेस्टी को 2020 में भारत में अपना संचालन बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। ग्रीनपीस इंडिया ने 2015 में एफसीआरए पंजीकरण रद्द होने के बाद अपने परिचालन को कम कर दिया है।

एक लाइनर

❖ शुक्रयान-1 भारत के पहले वीनस मिशन का नाम है। इसरो दिसंबर 2024 तक मिशन शुरू करने की उम्मीद कर रहा है।

❖ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने असम के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया। M15 पेट्रोल को पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है।

❖ भारत की रैंकिंग 'RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' में पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है।

❖ संतोष ट्रॉफी 2022 में पेनल्टी शूटआउट में बंगाल को हराकर केरल ने सातवीं बार खिताब अपने नाम किया।

❖ असम के डिब्रूगढ़ जिले में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया।

❖ गृह मंत्री, अमित शाह ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) परिसर का उद्घाटन किया।

❖ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया।

❖ एशियाई खेल 2022, जो सितंबर 2022 में हांग्जो, चीन में होने वाले थे, को बढ़ते COVID मामलों के कारण 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

❖ RBI ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) के तहत पॉलिसी रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट्स (bps) बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 4.00% था।

❖ ओडिशा भारत की एकमात्र वेधशाला बनाने की योजना बना रहा है, जो राज्य की स्वदेशी आबादी के स्वास्थ्य पर डेटा रखेगी।

❖ केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, आर.के. सिंह और जर्मन आर्थिक मामलों और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ रॉबर्ट हेबेक ने भारत-जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त घोषणा पर वस्तुतः हस्ताक्षर किए।

❖ परिसीमन आयोग, जिसने जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार किया, की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की।

❖ आरपीएफ ने 5 से 30 अप्रैल 2022 तक "ऑपरेशन सतरक" के तहत एक केंद्रित प्रयास शुरू किया।

CS Mentors IAS Academy

- फ्रांस में होने वाली मार्चे डू फिल्म में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा।
- नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज (जीआईएसएस) के एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनज्वेग को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण एनएफएचएस-5 के अनुसार, कुल प्रजनन दर (टीएफआर), प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।
- तेलंगाना राज्य सरकार ने 'नेथन्ना बीमा' (बुनकर बीमा) योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों को बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है।
- स्थानीय मीडिया के अनुसार, केरल ने कोल्लम शहर में टमाटर बुखार के कम से कम 82 मामले दर्ज किए हैं। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करने वाले लाल फफोले का कारण बनता है।
- हरियाणा 4 से 13 जून तक पंचकूला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार गतका, थांग-टा, कलारिपयट्टू, मल्लखंब और योगासन जैसे पांच पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। खेलों का शुभंकर धाकड़ है।
- भारतीय तटरक्षक बल ने कोच्चि के नेदुंबस्सेरी में तटरक्षक वायु एन्क्लेव में अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन '845 स्क्वाड्रन (सीजी)' कमीशन किया।
- भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब (FCT हब) हैदराबाद में डॉ रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज (DRILS) में स्थापित किया गया है।
- पंजाब सरकार ने हाल ही में चावल की सीधी बुवाई (डीएसआर) का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1,500 रुपये प्रोत्साहन की घोषणा की।
- दिल्ली और मेरठ के बीच भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस), हैदराबाद में वैश्विक गतिशीलता प्रदाता एल्सटॉम द्वारा डिजाइन किया जा रहा है और सावली, गुजरात में निर्मित किया जा रहा है।
- जॉन ली को एक चुनाव समिति द्वारा हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया, जिन्होंने गुप्त मतदान में अपना वोट डाला। समिति में लगभग 1,500 बड़े पैमाने पर बीजिंग समर्थक सदस्य शामिल थे।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने कम आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए "किफायती कनेक्टिविटी कार्यक्रम" शुरू किया है।
- तमिलनाडु मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

CS Mentors IAS Academy